

गन्ने हेतु अतिरिक्त भुगतान

प्रलिस के लयः

गन्ना, उचतऱ और लाभकारी मूल्य (Fair and Remunerative Price- FRP)

मेन्स के लयः

कृषऱ मूल्य नरऱधारण, भारतीय अरथवयवसुथा में चीनी उत्पादन, गन्ना उद्योग के समकष चुनौतयऱँ

चरुा में कयऱँ?

भारत सरकार ने सहकारी चीनी मलऱँ दवारा कसऱनों को गन्ना हेतु कयऱँ गए अतिरिक्त मूल्य भुगतान को "व्यावसायकऱ वयय" के रूप में दावा करने की अनुमताऱऱदान करके एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है ।

गन्ने हेतु अतिरिक्त भुगतान का मुद्दा:

- गन्ना भारत में एक प्रमुख फसल है, खासकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमलिनाडु जैसे राजयऱँ में ।
- केंद्र प्रत्येक वर्ष गन्ने के लयऱँ **उचतऱ और लाभकारी मूल्य** नरऱधारतऱ करता है, यह चीनी मलऱँ दवारा कसऱनों को उनके गन्ने की खरीद के लयऱँ भुगतान की जाने वाली न्यूनतम राशऱँ है ।
- हालाँकऱँ कुछ सहकारी चीनी मलऱँ, वशऱँ रूप से महाराष्ट्र में कसऱनों को प्रोत्साहन अथवा बोनस के रूप में FRP से अधकऱँ का भुगतान करती हैं । इसे अतिरिक्त गन्ना भुगतान (**Excess Cane Payment**) कहा जाता है ।
- इस अतिरिक्त गन्ना भुगतान के कारण सहकारी चीनी मलऱँ और आयकर वऱँभऱँ के बीच कर ववऱँद खड़ा हो गया है ।
 - ये मलऱँ अतिरिक्त भुगतान का दावा व्यावसायकऱँ वयय के रूप में करती हैं, जबकऱँ वऱँभऱँ इसे मुनाफे का वऱँतरण मानता है और इन पर कसऱँ भी प्रकार की छूट की अनुमताऱँ नहीं देता है ।

ववऱँद नऱँपऱँन की प्रकरयऱँ:

- भारत सरकार ने वऱँतऱँ अधनऱँयऱँम में संशोधन करते हुए वर्ष 2015-16 के केंद्रीय बजट में सहकारी चीनी मलऱँ को अपनी व्यावसायकऱँ आय की गणना के लयऱँ कऱँतौती के रूप में अतिरिक्त गन्ना भुगतान का दावा करने की अनुमताऱँ दी । हालाँकऱँ यह 2016-17 मूल्यांकन वर्ष से लागू कयऱँ गया था ।
- भारत सरकार ने सत्र 2023-24 के केंद्रीय बजट में सत्र 2015-16 से पहले के सभी वऱँतऱँतीय वर्षों के लयऱँ कऱँतौती के लाभ में वृद्धकऱँ है । यह आयकर अधनऱँयऱँम की धारा 155 में संशोधन कर कयऱँ गया था ।
- इस कदम से वऱँतऱँतीय वर्ष 2015-16 से पहले कयऱँ गए भुगतान के संबंघ में लंबतऱँ कर मांगों और मुकदमेबाज़ऱँी के वरऱँद्ध सहकारी चीनी मलऱँ को लगभग 10,000 करोड़ रुपए की राहत मलऱँने की उम्मीद है ।

उचतऱँ और लाभकारी मूल्य (FRP):

- परचयः
 - यह सरकार दवारा नरऱँधारतऱँ मूल्य है, चीनी मलऱँ कसऱनों से गन्ने की खरीद इस मूल्य पर करने को बाध्य है ।
- भुगतान और समझऱँताः
 - मलऱँ को कानूनी तौर पर कसऱनों से खरीदे गए गन्ने के लयऱँ उन्हें FRP का भुगतान करना आवशुयक है ।
 - मलऱँ कसऱनों के साथ समझऱँते पर हसुताकषर करने का वकऱँल्प चुन सकती हैं, जसऱँसे उन्हें कऱँशऱँतों में FRP का भुगतान करने की अनुमताऱँ मलऱँ सके ।
 - वलऱँंबतऱँ भुगतान पर प्रतऱँवऱँष 15% तक का बयऱँज शुल्क लग सकता है और चीनी आयुकुतऱँ, मलऱँ की संपत्तऱँयऱँँ को संलग्न करके भुगतान न कयऱँ गये FRP की वसूली कर सकते हैं ।

■ शासी वनियम:

- गन्ने का मूल्य निर्धारण **आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA), 1955** के तहत जारी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के वैधानिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है।
- नयियों के मुताबिक, FRP का भुगतान गन्ना डिलीवरी के 14 दिनों के अंदर किया जाना चाहिये।

■ निर्धारण एवं घोषणा:

- FRP का निर्धारण **कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP)** की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है।
- **आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA)** ने FRP की घोषणा की।
- FRP की घोषणा आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (CCEA) द्वारा की जाती है।

■ वित्तीय कारण:

- FRP में वित्तीय कारणों को ध्यान में रखा जाता है जिसमें **गन्ना उत्पादन की लागत, वैकल्पिक फसलों से प्राप्त नधि, कृषि वस्तुओं की कीमतों में रुझान, उपभोक्ताओं को चीनी की उपलब्धता, चीनी का बिक्री मूल्य, गन्ने से चीनी की रकवरी और गन्ना उत्पादकों के लिये आय सीमा** शामिल है।



Prices of Sugarcane are determined by Central and State Government.



Fair and Remunerative Price (FRP)

- The Central Government announces FRP which are determined on the recommendation of the CACP and announced by the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA).
 - The FRP is based on the Rangarajan Committee report on reorganising the sugarcane industry.



State Advised Prices (SAP)

- The SAP is announced by the Governments of key sugarcane producing states.
 - The price is calculated by the experts, who calculate the entire economics of the crop by taking input cost and then suggest to the government, which may agree or not.

#EconomyAndEndeavour

//

गन्ना:

